फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 309 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 12 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 219 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 12 जून, 2026 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल तथा सोनिया से मिले ममता एवं अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के सामने ममता बनर्जी को राज्यसभा में भेजने और सदन में विपक्ष का नेता बनाने का विकल्प पेश किया

- इसी बीच खबर है कि तृणमूल के बागी गुट से तकरीबन आधा दर्जन सांसद पुनः ममता बनर्जी के पक्ष में आ गए हैं।
- अगर ऐसा होता है तो बागी गुट के पास दो तिहाई से कम सांसद रह जाएंगे जो दलबदल कानून के तहत अलग गुट के रुप में मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यक है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जून। क्या ममता बनर्जी राज्यसभा में प्रवेश करेंगी और इसके बाद कांग्रेस की मदद से सदन में विपक्षी नेता के पद तक पहुँच जाएँगी?

ऐसी संभावनाओं पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा चल रही है।

विधानसभा चुनाव में जबरदस्त पराजय के बाद, अभूतपूर्व आंतरिक संकट का सामना कर रहा टीएमसी नेतृत्व दो मोर्चों पर काम कर रहा है: एक तरफ़ विधायकों और सांसदों के बीच विद्रोह को काबू में करना, और दूसरी तरफ़ पार्टी को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करना। समझा जाता है कि यह विचार (ममता के राज्यसभा में प्रवेश और सदन में विपक्षी नेता के रूप में पदोन्नति) ममता के भतीजे और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुई अपनी बैठक में प्रस्तुत किया था। ममता खुद एक दिन पहले सोनिया गांधी से मिली थीं। कहा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

टीएमसी के विद्रोही समूह की नेता काकोली घोष दास्तिदार द्वारा पार्टी से अलग हुए 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त होने की सनसनीखेज घोषणा के बाद, विद्रोही शिविर की गति थोड़ी धीमी होती लग रही है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल, जिन्हें विद्रोही शिविर अपना समर्थक मान रहा था, ने अलग हुए समूह से दूरी बना ली है। इसके अलावा, लगभग आधा दर्जन और सांसदों की पार्टी में वापसी की भी रिपोर्टें हैं। यदि ऐसा होता है, तो विद्रोही समूह के पास आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से काफी कम समर्थन रह जाएगा, जैसा कि दल-बदल विरोधी कानून में प्रावधान है।

कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि टीएमसी का आंतरिक संकट गंभीर नहीं है। हाल ही में पार्टी से दिये गये उच्च स्तरीय इस्तीफों में राज्यसभा सांसद सुखेन्दु सरकार राय और सुष्मिता देब शामिल हैं, जिससे राज्यसभा में टीएमसी सदस्यों की संख्या घट कर 11 रह गई है। इधर पता चला है कि पार्टी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्हें ममता का नज़दीकी सहयोगी माना जाता है, ने भी टीएमसी सुप्रीमो को अल्टीमेटम दिया है: "मुझे चुनें या अभिषेक बनर्जी को।" कल्याण ने गुरुवार को अभिषेक की आलोचना करते हुए, सार्वजनिक रुप से कहा कि ममता के भतीजे और पार्टी के महासचिव "अहंकारी" हैं और "सोचते हैं कि सभी उनके नीचे हैं।"

म.प्र. से भाजपा ने राज्यसभा की तीनों सीटें जीती

भोपाल, 11 जून। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत ली हैं। पार्टी के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को गुरुवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

- नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया व सर्टिफिकेट भी दे दिए गए।

राज्यसभा निर्वाचन के तय कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारी से नाम वापसी का गुरुवार को अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा के तीन उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिषेक बनर्जी प.बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए

इससे पहले अभिषेक को तीन बार सीआईडी ने बुलाया था पर वे नहीं गए थे

- सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अभिषेक ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए स्पीकर को जो पत्र लिखा था उसमें कितने विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर थे तीन विधायकों ने तो दावा किया है कि पत्र पर उनके साइन नहीं हैं।
- अगर यह आरोप साबित हो गया तो अभिषेक को सात साल की जेल हो सकती है।
- विधानसभा चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी को भाव नहीं मिल रहा है, कई नेता उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं।
- ममता जी भी बेहद शांत हो गई हैं पूर्व में दिल्ली से लौटने पर वे गंभीर टिप्पणियां करती थीं पर इस बार वे एयरपोर्ट से चुपचाप निकल गईं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11जून। विधानसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने में पेश हुए। इससे पहले वे तीन बार सीआईडी के सामने पेश होने से बच चुके हैं।

दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद, वे कोलकाता लौटे और वहां से उन्हें राज्य की सबसे चर्चित जांच एजेंसी के समक्ष पेशी के लिए ले जाया गया।

पुलिस की जांच शाखा यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या विपक्ष के नेता के नाम का प्रस्ताव भेजने से पहले उन्होंने वास्तव में 70 विधायकों की सहमति ली थी। तीन विधायक पहले ही कह चुके हैं कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में बादल छाये, भीषण गर्मी से राहत

दो दिन तेज आंधी, बारिश की संभावना

नई दिल्ली, 11 जून। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवा चलने लगी। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिली। इस बदलाव से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत का अहसास हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है।

आईएमडी के मुताबिक, 12 जून को आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बारिश और हवा के असर से तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

'कर्नाटक के मुख्यमंत्री का महा कचरा घोटाला'

भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कचरा प्रबंधन में 39,000 करोड़ रूपए के घोटाले का आरोप लगाया

- भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि कचरा प्रोसेस करने के लिए दी जाने वाली टिपिंग फीस 260 रूपए से बढ़ाकर 2400 रूपए कर दी गई है यानि 950 प्रतिशत वृद्धि। उन्होंने करदाताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार कर रहे हैं, पर एक कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट के माध्यम से करदाताओं को भारी नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि इस परियोजना की लागत में भारी वृद्धि हुई है और दावा किया कि कुछ विशेष संस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिये निविदा (टेंडर) प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में पूनावाला ने इस प्रोजेक्ट को "महा कचरा घोटाला" बताया और इसे उन विवादों की श्रृंखला से जोड़ा, जिनमें भाजपा पहले भी कांग्रेस सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाती रही है। उन्होंने लिखा, "कर्नाटक में बड़ा कचरा घोटाला! एमयूडीए घोटाला, ठेकेदार घोटाला, आवास घोटाला, शराब घोटाला और भूमि घोटाला के बाद, अब कांग्रेस का 39,000 करोड़ रुपये का कचरा घोटाला सामने आया है।" पूनावाला के अनुसार, कचरा प्रसंस्करण (वेस्ट प्रोसेसिंग) के लिए दी जाने वाली टिपिंग फीस लगभग 260 रुपये प्रति टन से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला'

वॉशिंगटन, 11 जून। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन जोरदार हमले हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द अमेरिका ईरान के तेल और गैस उद्योग पर अपना पूरा कब्जा जमा लेगा। इसमें ईरान का सबसे मुख्य तेल केन्द्र खर्ग द्वीप भी शामिल है। दोनों देशों के बीच यह भीषण लड़ाई गुरुवार सुबह तक चलती रही। अमेरिकी सेना का यह हमला पिछले दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा, तेज और आक्रामक था। इस हमले से ईरान को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ, ईरान ने अपने नुकसान की पूरी जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन कहा कि उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया है।

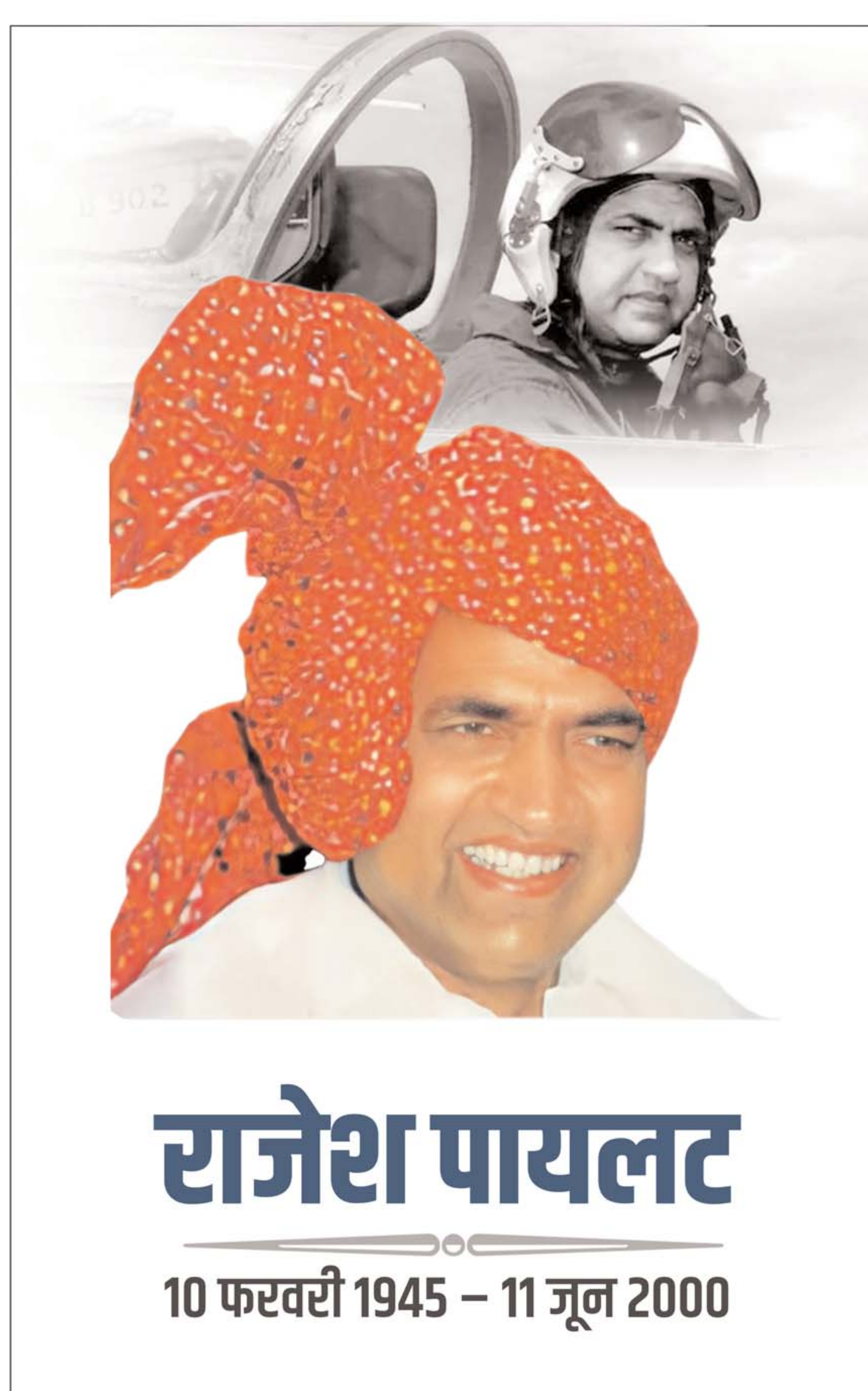

प्र.मंत्री ने नीति आयोग की बैठक ली

मीटिंग में पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

नई दिल्ली, 11 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में अल-नीनो की संभावित चुनौतियों को देखते हुए जल संरक्षण तथा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने का आव्हान किया।

उन्होंने आकांक्षी जिलों के मानकों के आधार पर प्रगति के मूल्यांकन और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए स्पष्ट निगरानी व्यवस्था, 100-दिवसीय तथा पांच वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर जोर दिया।

नीति आयोग की शीर्ष बैठक में पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। इस साल का विषय 'विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' था। इसमें 28 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची कांग्रेस

कांग्रेस का दावा नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है

- कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ शिकायत की और तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की।
- मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी महेश केवट के वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया या चुनाव नतीजे घोषित करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11जून। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नामांकन को रद्द किए जाने के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है।

यह कानूनी कदम तब उठाया गया, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, नटराजन के नामांकन पत्र खारिज कर दिए। सत्ताधारी पार्टी का दावा था कि कांग्रेस नेता ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में तेलंगाना के एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी।

लेकिन, नटराजन ने इन आरोपों को "राजनीतिक साजिश" करार देते हुए जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और यह मुद्दा केवल एक निजी शिकायत से संबंधित था।

बुधवार को नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) कम्प्रोमाइज़्ड थे। वे वर्तमान सरकार के प्रवक्ताओं और फ्रंटल संगठन प्रमुखों की तरह काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी कि कल रिटर्निंग ऑफिसर "कम्प्रोमाइज़्ड" थे। वे वर्तमान सरकार के प्रवक्ताओं और फ्रंटल संगठन प्रमुखों की तरह काम कर रहे थे।"

कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने और इसे "पूरी तरह से गलत, साफ तौर पर मनमाना एवं गैर कानूनी" आदेश बताते हुए, रद्द करने का अनुरोध किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)